

देवमुनि शर्मा

बनाम

झारखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 718, 2003)

26 मई 2009

[वी.एस. सिरपुरकर और आर.एम. लोढ़ा, जेजे]

दंड संहिता, 1860: धारा 307 नियम डब्ल्यू. उपधारा 149, 147, 148 - शस्त्र अधिनियम, 1959 - उपधारा 27, 5 और 7 - ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि - स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई कि अपीलकर्ता ने केवल डराने के विचार से हवा में गोली चलाई थी हमलावरों और संपत्ति और जीवन की निजी रक्षा के अधिकार के अनुसरण में और आरोपी 3 ने गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप 2 की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए - अपील पर, माना गया: अपीलकर्ता के कार्य से पता चला कि वह गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं था - धारा 149 के संबंध में निष्कर्ष विफल होना चाहिए - धारा 307 के तहत दोषसिद्धि बनाए रखने योग्य नहीं हैं क्योंकि यह कार्य आरोपी 3 द्वारा गोलीबारी करके व्यक्तिगत रूप से किया गया था - शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि का भी कोई परिणाम नहीं होगा - धारा 27 के तहत दोषसिद्धि को आमंत्रित करने के लिए, यह करना होगा साबित किया जाए कि आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल धारा 5 या 8, धारा 7 के उल्लंघन में किया गया था - धारा 7 लागू नहीं होती क्योंकि यह एक लाइसेंसी बंदूक थी - हमलावर को डराने के लिए हवा में फायरिंग करने के आरोपी की ओर से कार्रवाई भी इस दायरे में नहीं आएगी। धारा 5(1) की शरारत।

ट्रायल कोर्ट ने धारा 307 नियम डब्ल्यू के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। धारा 149 आईपीसी के साथ उपधारा 147 और 148 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27। जिस धारा 302 का उन पर आरोप लगाया गया था, उसके तहत उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था। अन्य आरोपियों को धारा 302 आर.डब्ल्यू. के तहत दोषी ठहराया गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की उप धारा 149, 147 और 148 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27। उच्च न्यायालय ने माना कि अन्य

आरोपी व्यक्तियों ने निजी बचाव के अधिकार का उल्लंघन किया और आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत अपराध की सजा को बदल दिया, हालांकि धारा 307 आर के तहत अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि की। डब्ल्यू उप धारा 149, 147, 148 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि अपीलकर्ता ने केवल हमलावरों को डराने के इरादे से हवा में गोली चलाई ताकि वे तितर-बितर हो जाएं। नीचे की अदालतों का निष्कर्ष यह था कि केवल आरोपी नंबर 3 और 4 ने ही गोलीबारी की थी। इसलिए अपील.

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. नीचे की अदालतों के निर्णयों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया था और न ही किसी अभियोजन गवाह के मामले में अपीलकर्ता ने गोली चलाई थी। आरोपी नंबर 3 ने ही गोली चलाई थी. फिर, जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, गैरकानूनी जमावड़े के संबंध में निष्कर्ष को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है। भीड़ को देखकर, अपीलकर्ता और अन्य आरोपी घर में घुस गए और आग्नेयास्त्रों के साथ वापस आए और तब भी अपीलकर्ता ने हवा में गोलीबारी की, जो उच्च न्यायालय के अनुसार केवल हमलावरों को डराने और तितर-बितर करने के उद्देश्य से थी। उन्हें। उस क्षण तक कम से कम अपीलकर्ता गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं था और न ही उस सभा को किसी निश्चित सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा कहा जा सकता है। यदि अंततः उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अन्य आरोपी व्यक्तियों ने निजी बचाव के अपने अधिकार के अनुसरण में गोलीबारी की, तो उनके इस कृत्य को गैरकानूनी सभा के लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर आईपीसी की धारा 149 के संबंध में निष्कर्ष विफल होना चाहिए और इसके साथ ही आईपीसी की धारा 147 और 148 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि भी होनी चाहिए। एक बार जब वह परिणाम प्राप्त हो जाता है, तो अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने का कोई सवाल ही नहीं है, जो जाहिर तौर पर अकेले आरोपी नंबर 3 द्वारा घायलों पर गोलीबारी करके किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि धारा 304 भाग 1 के तहत अपराध आरोपी संख्या 3 और 4 द्वारा व्यक्तिगत रूप से और काफी हद तक अकेले ही किया गया था। यह गैरकानूनी जमावड़े के किसी उद्देश्य के अनुसरण में नहीं था क्योंकि वहां कोई गैरकानूनी जमावड़ा था ही नहीं। इसलिए, अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 के तहत अपराध का मामला भी दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उसे उस अपराध से बरी किया जाना चाहिए। [पैरा 15]

2. एक बार उच्च न्यायालय का यह स्पष्ट निष्कर्ष है कि अपीलकर्ता ने केवल हमलावरों को डराने के लिए और अपनी संपत्ति और जीवन की निजी रक्षा के अधिकार के अनुसरण में हवा में गोलीबारी की और एक बार ऐसा हो गया। यह साबित हो गया कि उसे भी कुछ चोटें आईं, हालांकि सतही तौर पर, केवल उस उद्देश्य के लिए बंदूक का इस्तेमाल शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत कवर नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि भले ही उसने हवा में गोली चलाई हो, यह हमलावरों को डराने के विचार से था। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह भी पाया कि आरोपी व्यक्तियों के पास प्लॉट नंबर 97 था और उनके खिलाफ कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया गया था और न ही ऐसा कोई निषेधाज्ञा आदेश अदालत के समक्ष पेश किया गया था या साबित किया गया था। यदि ऐसा होता, तो अपीलकर्ता की कार्रवाई में आपराधिकता का रंग नहीं होता और इसलिए शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत उसकी दोषसिद्धि का भी कोई परिणाम नहीं होता। ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले में धारा 27, आर्म्स एक्ट के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। इस बात पर कोई साक्ष्य चर्चा नहीं की गई है कि आग्नेयास्त्र का उपयोगकर्ता शस्त्र अधिनियम की धारा 5 की शरारत के अंतर्गत कैसे आ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, धारा 5 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। शस्त्र अधिनियम फिर, अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं था कि इस अपीलकर्ता के पास उस राइफल का लाइसेंस नहीं था जिसका इस्तेमाल उसने हवा में फायरिंग करके किया था। शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि को आमंत्रित करने के लिए, यह साबित करना होगा कि आग्नेयास्त्र का उपयोग शस्त्र अधिनियम की धारा 5 या धारा 7 के उल्लंघन में किया गया था। चूंकि यह एक लाइसेंसी बंदूक थी, इसलिए धारा 7 के दायरे में आने का कोई सवाल ही नहीं था। जहां तक धारा 5 का सवाल है, हमलावरों को डराने के लिए हवा में फायरिंग करने का आरोपी का कृत्य धारा 5 के दायरे में नहीं आएगा। (1) शस्त्र अधिनियम. इसलिए, अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध से भी बरी किया जाना चाहिए। [पैरा 16 और 17]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2003 की सिविल अपील संख्या 718।

1996 (आर) की आपराधिक अपील संख्या 122 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.9.2002 से।

एस. चंद्र शेखर और मनोज कुमार।

उत्तरदाताओं के लिए मनीष कुमार सरन।

न्यायालय का निर्णय वी.एस. सिरपुरकर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलकर्ता यहां भारतीय दंड संहिता की धारा 149, 147 और 148 के साथ पठित धारा 307 के तहत अपराध के लिए अपनी सजा को चुनौती देता है और साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत भी। प्रारंभ में, अपीलकर्ता पर चार अन्य लोगों के साथ आईपीसी की धारा 147 और 148 के साथ-साथ धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

2. एक भ्रमित फैसले से, मूल आरोपी नंबर 2- राम प्रवेश शर्मा, आरोपी नंबर 3-बिजय शर्मा, और आरोपी नंबर 4-अजय शर्मा को आईपीसी की धारा 149, 147 और 148 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। . और ट्रायल कोर्ट द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 27। देवमुनी शर्मा, जो आरोपी नंबर 1 थे, को बिमल कुमार-आरोपी नंबर 5 के साथ धारा 307 के साथ धारा 149, 147 और 148 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध का दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। धारा 307 के तहत अपराध के लिए 10 साल और धारा 27, शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध के लिए 7 साल का कठोर कारावास।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, मूल आरोपी नंबर 2- राम प्रवेश शर्मा को उसकी जमानत की याचिका के आधार पर बरी कर दिया गया था। आरोपी नंबर 3-बिजय शर्मा और आरोपी नंबर 4-अजय शर्मा को आईपीसी की धारा 304 भाग | के तहत दोषी ठहराया गया। हालाँकि, उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत बरी कर दिया गया। उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। धारा 307 के तहत अपराध के लिए बिमल कुमार की सजा भी घटाकर सात साल कर दी गई। धारा 27, शस्त्र अधिनियम के तहत सजा को घटाकर तीन साल कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अपीलकर्ता देवमुनि शर्मा, आरोपी नंबर 1 के संबंध में कोई अलग आदेश पारित नहीं किया गया है।

4. संक्षेप में, हालांकि आरोपी नंबर 1 देवमुनि शर्मा को धारा 149 के साथ पढ़ी गई धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था और केवल आरोपी नंबर 5 बिमल कुमार के साथ धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, उच्च न्यायालय ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसे दोषी ठहराया गया हो। वास्तव में धारा 302 के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसकी गैर-मौजूद दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 भाग में बदल दिया गया और उसकी सजा को घटाकर सात साल कर दिया गया। संक्षेप में, उच्च न्यायालय ने यह महसूस करने की भी जहमत नहीं उठाई कि देवमुनि शर्मा को केवल आईपीसी की धारा 149

के साथ पढ़ी गई धारा 307 के संबंध में अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, न कि धारा 302, आईपीसी के तहत।

5. फिर, सत्र न्यायाधीश ने हालांकि अपने फैसले के पैरा 37 में कहा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह की छाया से परे अपना मामला साबित कर दिया है, केवल अजय शर्मा, बिजय शर्मा और राम प्रवेश शर्मा को दोषी ठहराया और वर्तमान देवमुनि शर्मा को दोषी नहीं ठहराया। अपीलकर्ता, धारा 302 के तहत अपराध का जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था लेकिन उसे आईपीसी की धारा 307/149, 147 और 148 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। ट्रायल कोर्ट ने इस अपीलकर्ता देवमुनी शर्मा को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत अपराध से बरी करने के बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं किया था। परिणामस्वरूप, वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था और केवल धारा 147 और 148, आईपीसी के साथ धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दस साल की सजा और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए सात साल की सजा का सामना करना पड़ा, जिस सजा पर उच्च न्यायालय ने कभी भी इस गलत धारणा के तहत विचार करने की जहमत नहीं उठाई कि उसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। धारा 302 और निजी रक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया था। हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि पूरा रवैया सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों की ओर से बेहद लापरवाही भरा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इतना बड़ा भ्रम पैदा हुआ है।

6. आमतौर पर, हम मामले को वापस भेज देते लेकिन यह देखते हुए कि अपीलकर्ता 75 वर्ष का है, मामले को फिर से वापस भेजना व्यर्थ होगा और इसलिए, हम इस अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो अब संभवतः केवल इसके खिलाफ है धारा 307-पठित धारा 149, 147 और 148 आईपीसी और एम्स अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए सजा।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इन भ्रमित निष्कर्षों के आधार पर हमें संबोधित किया है।

8. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि यह अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्त ग्राम मौजा हीरापुर में अपने आम घर में रहते थे। प्लॉट नंबर 97, खाता नंबर. 17 इस घर से जुड़ा हुआ है। इस भूखंड संख्या 97 के कब्जे और स्वामित्व के संबंध में शिकायतकर्ताओं और आरोपी व्यक्तियों के बीच मुकदमा चल रहा था। 12.11.1994 को सुबह लगभग 7 बजे आरोपी व्यक्तियों ने विवादित

भूमि पर ईंट निर्माण शुरू कर दिया और इस तरह शुरू हो गया। उस भूमि की प्रकृति को बदलना। यह जानकारी मिलने पर, हरिहर सिंह और उनके चाचा जनार्दन सिंह उर्फ छेदी सिंह वहां गए और आरोपियों को इस आधार पर रोका कि वे अदालत के निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। आरोपियों ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। वर्तमान अपीलकर्ता देवमुनी सिंह ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। सुशील कुमार सिंह, उनके चचेरे भाई मनोज सिंह, उनके दादा राम गोविंद सिंह, शंकर सिंह, नंदजी यादव, महंथ यादव जैसे कुछ अन्य लोग भी मौके पर आए और मामले को शांत करने की कोशिश की लेकिन आरोपी नहीं रुके, बल्कि वे सभी अंदर चले गए उनके घर और आग्नेयास्त्रों से लैस होकर वापस आये। जबकि आरोपी अजय शर्मा और बिजय शर्मा और वर्तमान अपीलकर्ता देवमुनि शर्मा राइफल से लैस थे, जबकि बिमल कुमार और राम प्रवेश शर्मा पिस्तौल से लैस थे। अपीलकर्ता ने हवाई फायरिंग की। लेकिन, अजय शर्मा और बिजय शर्मा ने हरिहर शर्मा और सुशील शर्मा पर गोली चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोप था कि रामप्रवेश शर्मा ने जनार्दन सिंह उर्फ छेदी सिंह और बिमल कुमार ने मनोज सिंह पर गोली चलायी थी उक्त जनार्दन सिंह की बाद में अस्पताल में मौत हो गयी जबकि मनोज सिंह घायल हो गये इसी आधार पर सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सत्र न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही की गई। माना जाता है कि मौके पर केवल दो आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि वर्तमान अपीलकर्ता सहित अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से आग्नेयास्त्र बरामद किये गये। आरोपी व्यक्तियों ने यह कहते हुए निजी बचाव के अधिकार का दावा किया कि उपरोक्त प्लॉट नंबर 97 उनका स्वामित्व था और उनके कब्जे में था और आरोपी व्यक्तियों ने स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकृति का कोई निषेधाज्ञा आदेश नहीं था। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि शिकायतकर्ता पक्ष, जिसकी संख्या अधिक थी, ने उनके घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उनके गहने उतारने की भी कोशिश की। उन्होंने यह भी बताया कि हमले में कम से कम तीन आरोपी घायल हो गए और इसलिए, उन्हें अपने बचाव के लिए आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करना पड़ा।

9. ट्रायल कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं था और आरोपी व्यक्तियों ने हत्या का अपराध किया था। हालाँकि, जैसा कि पहले कहा गया है, इसने हत्या के अपराध के लिए केवल तीन आरोपियों को दोषी ठहराया और वर्तमान अपीलकर्ता सहित शेष दो को आईपीसी की धारा 307/149, 147, 148 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया

गया। इस आधार पर कि उन्होंने अपने सामान्य उद्देश्य के लिए, मनोज सिंह को घायल कर दिया था।

10. हालाँकि, अपील में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी पक्ष को निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष दिया कि उपरोक्त प्लॉट नंबर 97 आरोपी पक्ष के कब्जे में था और आरोपियों को लगी चोटों के कारण उन्हें निजी बचाव का अधिकार था। यह भी पाया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ निषेधाज्ञा का कोई सबूत नहीं लाया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने निजी बचाव के अधिकार का उल्लंघन किया था। इसलिए, उनकी सजा को आईपीसी की धारा 304 भाग | के तहत अपराध में बदला जा सकता था। इस आधार पर, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, उन्हें सात साल की सज़ा दी गई। उच्च न्यायालय वर्तमान अपीलकर्ता के बारे में भ्रमित हो गया और उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसे सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 302 के तहत अपराध के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया। इसलिए, अब हमें इस बात पर विचार करना बाकी है कि क्या उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 149, 147 और 148 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 के तहत अपराध के लिए वर्तमान अपीलकर्ता की अपील को खारिज करने में सही था।

11. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप शिकायतकर्ताओं पर गोली चलाने का नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा कमजोर ढंग से यह सुझाव दिया गया कि उसने हवा में गोली चलाई थी और अन्य आरोपी व्यक्तियों को शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला करने के लिए उकसाया था।

12. उस भूमिका के बारे में उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 7 के अंत में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया है:

“कब हरिहर सिंह और सुशील सिंह की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देखें, | पता चला कि उनके सीने पर गोली का निशान पाया गया है। इसका मतलब है कि इरादा उनकी जिंदगी खत्म करने का था, लेकिन जैसा कि पीडब्ल्यू खुद कहता है कि देवमुनि शर्मा की ओर से हवा में फायरिंग भी की गई थी, जिससे पता चलता है कि पहले देवमुनि शर्मा की मंशा हमलावरों को तितर-बितर करने और डराने की थी, लेकिन फायरिंग के बाद भी हमलावर तितर-बितर नहीं हुए तो उन्होंने उनकी छाती पर निशाना साध लिया जाहिर है, छाती पर यह निशाना

निजी रक्षा के अधिकार से अधिक प्रतीत होता है। कम से कम महत्वपूर्ण भागों को निशाना बनाकर प्रतिकार करने का उद्देश्य पूरा किया जा सकता था। इस प्रकार | यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कथित घटना हुई थी लेकिन अपीलकर्ताओं ने निजी बचाव के अपने अधिकार का उल्लंघन किया।"

(जोर दिया गया)

13. वास्तव में, इस निष्कर्ष पर ही अपीलकर्ता, जो आरोपी नंबर 1 था, को अपराध से मुक्त कर दिया जाना चाहिए था। यदि स्पष्ट रूप से आरोपी नंबर 1 ने हमलावरों को डराने के लिए केवल हवा में गोली चलाई थी ताकि वे तितर-बितर हो जाएं तो उसने स्पष्ट रूप से कोई अपराध नहीं किया है। यह किसी का मामला नहीं था कि उसने दो मृत व्यक्तियों पर गोली चलाई थी। दोनों अदालतों के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि केवल आरोपी नंबर 3 और 4 ने ही गोली चलाई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता देवमुनि शर्मा की अपील को इस गलत धारणा पर खारिज कर दिया कि उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए पर्याप्त रूप से या धारा 149, आईपीसी की सहायता से दोषी ठहराया गया था, ट्रायल कोर्ट के फैसले पर एक नजर डालने से पता चलता है कि उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था। इसलिए दोषी ठहराया गया. ट्रायल कोर्ट ने उसे केवल आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय के फैसले का आधार ही खत्म हो गया है। अन्य अपीलकर्ता जिन्हें धारा 304 भाग के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। आईपीसी ने कोई अपील दायर नहीं की है और न ही अभियोजन पक्ष इस निष्कर्ष के खिलाफ अपील में आया है और इसके परिणामस्वरूप आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। इसलिए, यह निष्कर्ष अंतिम हो गया है। निष्कर्ष को वैसे ही पढ़ें जैसा कि निष्कर्ष के साथ है पैरा 9 में दिए गए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की सजा, जिसे विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा भी संदर्भित नहीं किया गया है, गलत है क्योंकि अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया था और यहां तक कि सत्र न्यायाधीश का निष्कर्ष भी गलत था। अभियोजन पक्ष द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई।

14. यह हमें आईपीसी की धारा 149, 147 और 148 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 के तहत सजा के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए उनकी सजा के संबंध में अनुत्तरित प्रश्न छोड़ देता है।

15. हमने निम्न न्यायालयों के निर्णयों को बहुत ध्यान से देखा है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है और न ही अभियोजन पक्ष के किसी गवाह का मामला है कि अपीलकर्ता ने मनोज सिंह पर गोली चलाई थी। गोली बिमल कुमार ने ही चलाई थी। फिर, जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का संबंध है, गैरकानूनी जमावड़े के संबंध में निष्कर्ष को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है। भीड़ को देखकर, अपीलकर्ता और अन्य आरोपी घर में घुस गए और आग्नेयास्त्रों के साथ वापस आए और तब भी अपीलकर्ता ने हवा में गोलीबारी की, जो उच्च न्यायालय के अनुसार केवल हमलावरों को डराने और तितर-बितर करने के उद्देश्य से थी। उन्हें। उस क्षण तक कम से कम अपीलकर्ता गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं हो सकता है और न ही सभा को किसी निश्चित सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा कहा जा सकता है। यदि अंततः उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अन्य आरोपी व्यक्तियों ने निजी बचाव के अपने अधिकार के अनुसरण में गोलीबारी की, तो उनके इस कृत्य को गैरकानूनी सभा के लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर आईपीसी की धारा 149 के संबंध में निष्कर्ष विफल होना चाहिए और इसके साथ ही आईपीसी की धारा 147 और 148 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि भी होनी चाहिए। एक बार जब वह परिणाम प्राप्त हो जाता है, तो अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने का कोई सवाल ही नहीं है, जो स्पष्ट रूप से अकेले बिमल कुमार द्वारा मनोज सिंह पर गोली चलाकर किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अपराध धारा 304 भाग | आरोपी संख्या 3 और 4, अजय शर्मा और बिजय शर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से और काफी हद तक अकेले ही अपराध किया गया था। यह गैरकानूनी जमावड़े के किसी उद्देश्य के अनुसरण में नहीं था क्योंकि वहां कोई गैरकानूनी जमावड़ा था ही नहीं। इसलिए, वर्तमान अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 307 के तहत अपराध का मामला भी दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उसे उस अपराध से बरी किया जाना चाहिए।

16. एक बार उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता ने केवल हमलावरों को डराने और अपनी संपत्ति और जीवन की निजी रक्षा के अधिकार के अनुसरण में हवा में गोली चलाई और एक बार यह साबित हो गया कि उसने भी कुछ चोटें लगीं, भले ही सतही, केवल उस उद्देश्य के लिए बंदूक का उपयोग शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत कवर नहीं किया जा सकता। वास्तव में, हमें अभियोजन पक्ष की बात पर संदेह है कि उसने हवा में बंदूक चलाई और अन्य आरोपियों को हमला करने के लिए उकसाया। अभियोजन के इस मामले को उच्च न्यायालय ने गलत पाया है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि भले ही उसने हवा में गोली चलाई हो, यह हमलावरों को डराने के इरादे से था।

उच्च न्यायालय ने यह भी विशेष रूप से पाया है कि आरोपी व्यक्तियों के पास उपरोक्त प्लॉट नंबर 97 था और उनके खिलाफ कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया गया था और न ही ऐसा कोई निषेधाज्ञा आदेश अदालत के समक्ष पेश किया गया था या साबित किया गया था। यदि ऐसा होता, तो अपीलकर्ता की कार्रवाई में आपराधिकता का रंग नहीं होता और इसलिए शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत उसकी दोषसिद्धि का भी कोई परिणाम नहीं होता। ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले में धारा 27, आर्म्स एक्ट के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। इस बात पर कोई साक्ष्य चर्चा नहीं की गई है कि आग्नेयास्त्र का उपयोगकर्ता शस्त्र अधिनियम की धारा 5 की शरारत के अंतर्गत कैसे आ सकता है। हमारे समक्ष ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई और न ही अभियोजन पक्ष के विद्वान वकील द्वारा इस मुद्दे पर हमसे संपर्क किया गया। ऐसी परिस्थितियों में, हम शस्त्र अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं। फिर, अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि इस अपीलकर्ता के पास उस राइफल का लाइसेंस नहीं था जिसका इस्तेमाल उस पर हवा में गोली चलाने के लिए करने का आरोप है।

17. शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि को आमंत्रित करने के लिए, यह साबित करना होगा कि आग्नेयास्त्र का उपयोग शस्त्र अधिनियम की धारा 5 या धारा 7 के उल्लंघन में किया गया है। चूंकि यह एक लाइसेंसी बंदूक थी, इसलिए धारा 7 के आने का कोई सवाल ही नहीं था। जहां तक धारा 5 का सवाल है, हमें नहीं लगता कि हमलावरों को डराने के लिए हवा में फायरिंग करने का आरोपी का कृत्य धारा 7 के दायरे में आएगा। शस्त्र अधिनियम की धारा 5(1) की शरारत। इसलिए, अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध से भी बरी किया जाना चाहिए।

18. परिणामस्वरूप, ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई और उच्च न्यायालय द्वारा गलत पुष्टि की गई अपीलकर्ता की सजा कानून की नजर में खराब है और आरोपी बरी होने का हकदार है। उसे सहजता से बरी किया जाता है। निम्न दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाता है।

डीजी.

अपील की अनुमति।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।